पहल स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, राष्ट्र निर्माता के नाम की पट्टिका भी रहेगी

नए शिक्षा सत्र से ड्रेसकोड: महिला मैरून व पुरुष शिक्षक पहनेंगे ब्लू रंग की जैकेट

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

अब डॉक्टर और वकील की तरह प्रदेश के शिक्षक भी खास ड्रेसकोड में नजर आएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इस संबंध में मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिसे नए शिक्षा सत्र से लागू किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक ड्रेसकोड में स्कूल आएंगे। इसमें महिला मैरून और पुरुष शिक्षक ब्लू रंग की जैकेट पहनेंगे। साथ ही राष्ट्र निर्माता की नाम पट्टिका भी जैकेट पर लगी रहेगी।

इसका उद्देश्य बच्चों में नैतिक संस्कार का बोध कराना और राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षकों को पहचान दिलाना है। विभाग का मानना है कि अगर शिक्षकों में गणवेश की एकरूपता रहेगी तो बच्चे भी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इस संबंध में मप्र स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने आदेश जारी कर नए शिक्षा सत्र से लागू करने कहा है।

जिम्मेदारी का होगा अहसास

अधिकारियों के मुताबिक अगर शिक्षक राष्ट्र निर्माता की पट्टी में आएंगे तो उनमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास भी होगा, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य है, जिनका निर्माता शिक्षक को ही माना जाता है।

छात्रों की तरह शिक्षकों में भी एकरूपता

स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में एकरूपता दिखाने के लिए खास ड्रेसकोड में नजर आते हैं। वैसे ही अब शिक्षक भी जैकेट पहनकर एकरूपता में नजर आएंगे। साथ ही वकील, डॉक्टर जिस तरह से जैकेट में नजर आते हैं, वैसे ही अब शिक्षकों की भी अलग पहचान होगी।

अन्य राज्यों में भी ड्रेसकोड तय

मप्र के साथ कई अन्य राज्यों के स्कूलों में भी ड्रेसकोड तय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी आसमानी रंग की शर्ट और गहरे स्टील ग्रे रंग की पैंट पहनेंगे, जबकि महिला शिक्षक व अधिकारी आसमानी रंग की साड़ी या सूट में पहनेंगी। वहीं झारखंड में भी शिक्षकों के लिए ड्रेसकोड तय किया गया है।

शिक्षकों की अलग पहचान होगी

नए शिक्षा सत्र से शिक्षक गणवेश के साथ राष्ट्र निर्माता की पट्टी में नजर आएंगे। वकील, डॉक्टर की तरह अलग पहचान होगी। इसकी तैयारी चल रही है।

– **नीरज दुबे**, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय

स्कूलों में अब स्व सहायता समूहों के माध्यम वितरित होगा गणवेश

- समूहों की आय बढ़ाने के लिए शासन ने बनाई योजना
- शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी तक जानकारी देने के दिए निर्देश

भास्कर संवाददाता | खूजा

शासन की निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के तहत अब शासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को गणवेश वितरण स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से होगा। एसएचजी ही संबंधित स्कूल के बच्चों की यूनिफार्म की सिलाई करेंगे। इससे एसएचजी के सदस्यों को नया काम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी। यूनिफार्म वितरण के लिए एसएचजी की क्षमता का निर्धारण व उनका चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी 15 फरवरी तक राज्य तक राज्य शिक्षा केन्द्र तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उपलब्ध कराने के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में हाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने गणवेश वितरण की इस नई व्यवस्था को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लिंक किया है। मिशन द्वारा चिन्हित स्व सहायता समूह/संगठन ग्रामवार व शालावार गणवेश तैयार करने के लिए लक्ष्य निर्धारण करेंगे। व विकासखंड वार कुल प्रदाय किए जाने वाले गणवेश की संख्या का आंकलन करेंगे। कलेक्टर द्वारा यूनिफार्म वितरण के लिए केवल ऐसे एसएचजी को चुना जाएगा जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्रियाशीलता व कुशलता के साथ काम रहे हैं।

यह नई व्यवस्था इसी शिक्षा सत्र 2018-19 से लागू हो जाएगी। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग और एसआरएलएम के जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक भी जल्द आयोजित की जाएगी। फिलहाल शासन ने एसएचजी के माध्यम से गणवेश वितरण की व्यवस्था केवल कक्षा एक से आठवीं तक के शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए की है। प्रदेश में यह योजना विगत 17-18 सालों से चल रही है। अब तक यूनिफार्म सप्लाई का जिम्मा बुरहानपुर के पावरलूम बुनकर संघ के पास था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों यूनिफार्म मिलने व स्कूली छात्रों को उनके वितरण का काम स्व सहायता समूहों को दिए जाने की घोषणा कर क्रियान्वयन की दिशा में यह कदम उठाया है। इस योजना से छात्रों को भी फायदा होगा, उन्हें अच्छी क्वालिटी का गणवेश उपलब्ध होगा, साथ ही समय पर भी मिल सकेगा।